

# अखंड भारत संघर्षा

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार 25 दिसम्बर 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

## क्रियायोग संघर्ष

क्रियायोग आश्रम एवं  
अनुसंधान संस्थान  
प्रयागराज

**क्रियायोग:** साँच (सच Truth) को आँच नहीं। आँच अज्ञानता (अविद्या Ignorance) समय, दूरी वा सापेक्षता की अनुभूति है जो समस्त दुःखों का कारण है। अध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्य तरीके से जीवन जीने पर सच की अनुभूति के लिए व्याधि रहित लगभग दस लाख वर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रियायोग अभ्यास से सच की अनुभूति एक ही जन्म में सम्भव है।

- प्राचीन उच्च मानव सभ्यता में वर्णित यज्ञ, वर्तमान में विश्व विख्यात 'क्रियायोग' है।
- क्रियायोग अभ्यास वेदपाठ है, पूर्ण ज्ञान की अनुभूति है।
- क्रियायोग अभ्यास ईश्वर अनुभूति है।
- क्रियायोग अभ्यास अतीत, वर्तमान व भविष्य से जुड़ा है।
- क्रियायोग अभ्यास जीवन मृत्यु पर विजय है।

क्रियायोग से सभी  
प्रकार की समस्याओं  
का समाधान  
सुनिश्चित।



10 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष का विकास

## उपर में आज से लगेगा रात्रिकालीन कपर्यू, योगी सरकार ने की घोषणा

शादी विवाह जैसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोग हो सकेंगे शामिल



### महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केस 100 पार

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 20 नए संक्रमित मिलने के बाद ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई है। महाराष्ट्र के साथ मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में भी तेजी बढ़कर रही है। इसके बाद सरकार ने पांचदिवा का एलान कर दिया है। इसके तहत राज 9 बजे से अधिक लोगों की कुल संख्या 108 हो गई है। इनमें से 54 कारोड़ 41 लाख 94 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण और नौ कारोड़ 14 लाख से अधिक टीर्स्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतरक तार बरती जाए। निरागनी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सांख्यनीय कार्य किया है। तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी बांदों में निरागनी समितियों को पुनः एकिवेक्षण करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रैकिं की ट्रैसिंग कराएं। उनके रखायी पर सतरक नजर रखी जाए। अवश्यकतानुसार लोगों को बवानीनी किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशका को देखते हुए हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं। इस प्रकार टीकाकरण के लिए प्रदेश के खिलाफ मिलाया जाएगा। आज योगी ने कोविड से बचाव के लिए ट्रैसिंग, ट्रैस्टिंग, ड्रीटेंट और टीकाकरण की नीति के सही



क्रियान्वयन से प्रदेश में रिस्ति निर्धारित है। जीते 24 घंटों में हुए एक लाख 91 हजार 428 सैम्प्ल की जांच में कुल 49 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 12 लोग नहीं कोविड से बचाव के लिए ट्रैसिंग, ट्रैस्टिंग, ड्रीटेंट और टीकाकरण की नीति के सही

भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। सँझों, बाजारों में हर किसी के लिए। मारक अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एडिस सिस्टम को और प्रधारी बनाया जाए। देश के विवेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति को ट्रैसिंग-ट्रैस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतरक तार बरती जाए। निरागनी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सांख्यनीय कार्य किया है। तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी बांदों में निरागनी समितियों को पुनः एकिवेक्षण करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रैसिंग कराएं। उनके रखायी पर सतरक नजर रखी जाए। अवश्यकतानुसार लोगों को बवानीनी किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशका को देखते हुए हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं। इस प्रकार टीकाकरण के लिए ट्रैसिंग कराएं। आज योगी ने कोविड से बचाव के लिए ट्रैसिंग, ट्रैस्टिंग, ड्रीटेंट और टीकाकरण की नीति के सही

हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं हिंदुत्वावादी, कीमत चुकाता है हर समुदाय : राहुल गांधी नई दिल्ली। पंजास नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुत्वावादियों ने हमेशा नफरत और हिंसा फैलाई है, जिसकी कीमत हर समुदाय को चुकानी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दिसंकार के खिलाफ है और यह आगे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह बते हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद को लेकर कही है, जहां कथित तौर पर कई सतों और बिंदुवादी नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भर भाग दिया है। इस प्रदेश के खिलाफ नफरत भर बचानों के लेकर पुलिस की रडार पर है। राहुल गांधी ने ट्रीटीट किया, 'हिंदुत्वावादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं। हिंदु-मुसलमान-सिख-ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं। आज योगी ने कहा कि इस संदर्भ में उनको के द्वारा यह मंत्री अमित शाह से बात की जाए।



### पंजाब: लुधियाना कोर्ट परिसर विस्फोट मामले में छह लोग हिरासत में

चार्डीगढ़। एक दिन पूर्व लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने छह लोगों को पुछताले के लिए हिरासत की जांच के लिए टीम आयुक्त के संतुलित सिहं भूल्लर ने बताया कि इस मामले में पुलिस को अहम सुरक्षा दिया गया था। वह पले से ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसके खिलाफ नफरत भर बचानों के लेकर पुलिस की रडार पर है। राहुल गांधी ने ट्रीटीट किया, 'हिंदुत्वावादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं। हिंदु-मुसलमान-सिख-ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं। आज योगी ने कहा कि इस संदर्भ में उनको के द्वारा यह मंत्री अमित शाह से बात की जाए।

सीएम चन्नी ने मामले में केंद्र से मदद

केंद्र से इसकी जांच के लिए टीम दिल्ली से पहुंच रही है। इस लिए टीम की जांच केन्द्रीय एजेंसियों ही कर रही है। दूसरी ओर लुधियाना पुलिस प्रशासन ने अदालत परिसर में सुरक्षा सख्त कर दी है। आज एक व्यक्ति को पहली ओर और 45.66 पांसदी लोगों को दोनों ओर मिल चुकी है। वैक्सीनेशन को और तेज करने की जरूरत है। इस संबंध में जबकि 6 लोगों को दोनों ओर योगी ने कहा कि इसकी जांच के लिए टीम दिल्ली से पहुंच रही है। इनमें से 12 की जांच के लिए टीम दिल्ली के द्वारा कर रही है। इनमें से 54 कारोड़ 41 लाख लोगों ने एक व्यक्ति को पहली ओर दोनों ओर योगी ने कहा कि इस प्रकार टीकाकरण के लिए ट्रिप्पल एंटीबोडी विस्ट्रेटिंग की जाए। आज योगी ने कहा कि इस प्रकार टीकाकरण के लिए ट्रैसिंग कराएं। आज योगी ने कहा कि इस प्रकार टीकाकरण के लिए ट्रैसिंग, ट्रैस्टिंग, ड्रीटेंट और टीकाकरण की नीति के सही

में हुए बम विस्फोट मामले की जांच कर उसके कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी जाए।

जिला अदालत परिसर में बम विस्फोट को खड़ा कर रही है।

केंद्रीय विधि एवं धर्म मंत्री ने कहा कि उन्होंने का नाम गणनीय विस्फोट के कुछ घटे बाद केंद्रीय

परिसर के द्वारा किया गया है।

परिसर के द्वारा किया गया है।

जिला अदालत का दौरा किया गया है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच बहुत अंतर है।

उन्होंने कहा कि देश के साथ राज्यों में शक्ति और सद्व्यवहार के बीच









सम्पादकीय

## अयोध्या में राम नाम की लूट

उत्तरप्रदेश के चुनावों में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भाजपा अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगी थी। लेकिन मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले के आरोप में भाजपा फंस गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में फैसला दिया और मंदिर विवाद का रास्ता साफ हुआ तो उस के बाद खबर आई कि विधायकों, मेरयर, आयुक्त, एसडीएम और डीआईजी के रिश्तेदारों ने अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं। एक राष्ट्रीय अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जमीन महंगे दामों में ली गई हैं। वहाँ महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1990 के दशक की शुरूआत में, राम मंदिर स्थल से 5 किलोमीटर से भी कम दूर बरहटा मांझा गांव और अयोध्या में आसपास के कुछ अन्य गांवों में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया था, इस जमीन में से लगभग 21 बीघा जमीन कथित तौर पर दलितों से नियमों का उल्लंघन करते हुए खरीदी गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच बैठाई है। विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद मामले को लेकर जांच करेंगे और शासन को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंप देंगे। लेकिन अब यह मामला धार्मिक और कानूनी सरहदों से आगे बढ़ता हुआ राजनैतिक हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व की अपनी व्याख्या जोड़ा है। राहुल गांधी ने ट्रॉटर किया- हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चंदे की लूट' और 'जमीन की लूट' पर जवाब देना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए। जबकि उपर में कांग्रेस का जिम्मा संभाल रही प्रियंका गांधी ने इस मामले में एक प्रेस वार्ता में कहा कि पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया गया और अब दलितों की जमीन को हड्डा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी स्तर पर जांच हो रही है। जांच भी उच्च न्यायालय की निगरानी में की जानी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर को बनवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। देश भर में चंदा मांगा गया और सभी की भावनाएं हैं और

वे उन भावनाओं को आहत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के ये इल्जाम भले ही चुनावी गणित के हिसाब से लगाए गए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि राम के नाम पर लूट का खेल बीजेपी खेल रही है और यह अकेले अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा काशी तक फैल ही चुका है और शायद मथुरा तक भी यह बढ़ जाए। वैसे भी भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने पिछले दिनों बयान दिया है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जम्भूमि है और अब वहाँ उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। उनके पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कृष्ण मंदिर की बकालत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यागी बार-बार मथुरा के चक्कर काट रहे हैं। इधर काशी में पिछले दिनों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर ही चुके हैं। जिसमें भगवान की पूजा अर्चना के साथ-साथ पूजन सामग्री के व्यापार औ? श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस भव्यता की कीमत जनता की जेब से चुकाई जा रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के लिए पहले मामूली रकम लगती थी, लेकिन अब इसकी भी बाकायदा रेटलिस्ट जारी हो गई है। जिसका भुगतान कम से कम गरीब के लिए संभव नहीं है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा, तब भी रामलला तक पहुंचने के मौके और हक्क शायद अमीरों को ही मिलेंगे, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जेब ढीली कर भगवान का दर्शन भी विलासिता की तरह ही होगा। अब वो दिन शायद चले गए। जब भगवान दीनवत्सल हुआ करते थे। अब भगवान के नाम पर व्यापार इस कदर बढ़ गया है कि दीन-दुखियों की जगह केवल अमीरों की पहुंच भगवान तक हो गई है। मंदिरों में दर्शन, पूजा और प्रसाद के नाम पर व्यापार तो शुरू हो ही गया है, मंदिरों के नाम पर बने न्यासों में जो लाखों-करोड़ों की कमाई होती है, उस पर भी व्यापारियों की नजर टिकी रहती है। कई मंदिर ट्रस्ट अपने खर्च पर गरीबों की पढाई, इलाज जैसे काम करते हैं। मगर जिस तरह धर्म को धंधा बना लिया गया है, उसमें परोपकार के ये काम कितने देर तक चलेंगे, कहना कठिन है। अयोध्या में जिस तरह जमीन खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है, उसे भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों का एक संकेत समझना चाहिए। मगर ऐसा लगता नहीं कि भाजपा इस संकेत को देखना या समझना चाहती है। क्योंकि इससे उसकी हिंदूत्व की राजनीति मश्किल में पड़ जाएगी।

## जटिल है असमानता का विमर्शी

अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभ तभी हमारे श्रमिकों को मिल सकते हैं जब उनकी कुशलता में सुधार आए। किंतु अकुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमिकों को कुशल बनाने की आशा कम से कम निजी क्षेत्र से तो नहीं की जा सकती। जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को ही उठानी होगी। ऐसा लगा कि मोदी सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के आंकड़ों के बाद भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता फिर चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 प्रतिशत सर्वाधिक अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय के 57 प्रतिशत भाग पर कबिज थे। हमारे देश की आधी आबादी सिर्फ 13.1 फीसदी कमाती है। आर्थिक समानता हमारे सर्वेधानिक लोकतंत्र की समानता की अवधारणा को साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हाशिए पर धकेले गए समुदायों को समान अवसर और अधिक प्रतिनिधित्व मिले यह सुनिश्चित करने में आर्थिक समानता की बड़ी भूमिका है। आर्थिक असमानता अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना सकती है। इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे आवश्यक क्षेत्रों में निवेश में कमी आ सकती है। हाल में किए गए अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि कोरोना काल में घटती हुई मजदूरी और आय ने कुल मांग पर विपरीत प्रभाव डाला है क्योंकि आम लोगों के उपभोग में कमी आई है। अनेक आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार कम आय में जीवन बिताने वाले बहुसंख्य लोगों की इस दशा के लिए शीर्ष पर मौजूद मीठे भर लोगों के पास संपत्ति का एकत्रीकरण उत्तरदायी नहीं है। यदि इस विवादित स्थापना को स्वीकार कर भी लिया जाए तब भी इतना तो तय है कि शीर्ष के चंद लोगों के पास संपत्ति के एकत्रीकरण ने आम लोगों के जीवन स्तर और रहन-सहन तथा उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव डाला है। जहां तक भारत का संबंध है यहां आर्थिक गैरबराबरी के लिए केवल वितरण की असमानता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियां तथा श्रम बाजार में जातिगत भेदभाव वे कारक हैं जो दलितों का भूमि और संपत्ति तथा उनके श्रम के उचित मूल्य से वर्चित रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय पुणे, जैननगृह तथा ईडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज द्वारा 20 राज्यों के 110800 परिवारों को सम्मिलित करते हुए सन् 2015 से 2017 के मध्य किए गए अध्ययन के बाद संर्वाधित अध्ययनकर्ताओं ने

# मुझे कार्यकर्ता पद से कोई हटा नहीं सकता

प्रभात झा

नेता रहते हुए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भेजा था। जबकि ऐसी बैठकों में भारत का प्रधानमंत्री या अन्य ज्येष्ठ मंत्री ही नेता के रूप में जाते हैं, इस घटना से सारा विश्व चकित था। नरसिंहराव ने अपने एक भाषण में कहा था कि<sup>४</sup> अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अटलजी की जानकारी और विदेश मंत्री के तौर पर उनके अनुभव के कारण आज विश्व में वह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है।<sup>५</sup> भारत के राजनैतिक विशेषकों का मानना था कि अटलजी अगर दस वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का भविष्य कुछ और होता। आजादी के दूसरे दिन जो प्राथमिकताएँ तय होनी थीं, वह अटलजी के प्रधानमंत्री बनने तक तय नहीं हुई थीं।<sup>६</sup> सत्तान्तर-लोलुपता के ऊहापोह के बीच निर्विकार भाव से जनसेवा के लिए प्रस्तुत रहने का सामर्थ्य हर किसी में हो ही नहीं सकता। दलगत राजनीति के जंगलराज में अपने आप को निष्पक्ष रख पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है अटलजी विदेश मंत्री रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के

भारत रत्न अटल बिहारा वाजपेया जयता पर वशष  
महत्वपूर्ण भूमिका के दायित्व का निर्वाह करते हुए इन मर्यादाओं का पालन किया। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है प्रतिपक्ष में रहते हुए अटलजी रचनात्मक आलोचना के हिमायती थे रचनात्मक दृष्टिकोण तभी संभव है जब गहन अध्ययन, सभ्यता, बाह्य और संस्कृति के अंतरंग स्वरूप से सुपरिचित, जीवन मूल्यों के प्रति लगाव और मनुष्य-मनुष्य के बीच रागात्मक संबंधों की स्थापना का लगन हो अटलजी को प्रधानमंत्री बनने की यात्रा में सफलता की पुष्पमालाएँ ही नहीं मिलती रहीं, ऐसे क्षण भी आए जब एक तरफ जनसंघ के संस्थापक डॉ. मुखर्जी की 1953 में संदिग्ध मौत हो गई वहीं पंडित दीनदयालजी की दारुण और रहस्यमय हत्या हो गई। इसके बाद दल को घोर निराशा और वेदना के भंवर से उबारने वाले नाविक की भूमिका इन्हें निभानी पड़ी चुनावों को सफलता का एकमात्र मापदंड मानने वालों की दृष्टि में संसद में केवल दो स्थान, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में लड़े गए, प्राप्त हुए।

चुनाव में पाई गई तीन सीटों से भी कम थी, तब आस्था और विश्वास का संबल बनना पड़ा, ऐसे क्षण भी आए। अटलजी इसके बाद भी टूटे नहीं इसके बाद भी देशभर में प्रवास की अखंड धारा चली। संसद से सड़क तक संधर्ष जारी रखा। सन् 1984 में अटलजी ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे। वे उस चुनाव में पराजित हो गए। इसके बाद वे रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाने ग्वालियर आए, उस समय पत्रकार के नामे इस पर्कि का लेखक वहाँ उपस्थित था। हम सभी पत्रकार उनके पास पहुंचे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अटलजी से कहा, 'अपके भाषण सुनकर जनता के मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न होती है।' अटलजी ने त्वरित जवाब देते हुए कहा, 'भाषण में श्रद्धा और वोट में श्राद्धा।' यह सुनकर सभी पत्रकारों ने राजनीति की गहराई समझा। अटलजी मनोविज्ञान में बहुत गहरी बातें कह जाते थे। उन्होंने अपनी वाणी की शैली से अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारत के ऐसे राजनेता थे जिनकी सभा का संदेश

हुए प्रदर्शन कर रहे थे, सार्वजनिक मंच से सबक सिखा देने की चेतावनी दी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने 25 सितंबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने बारे में गर्व से बताते हुए कहा था- 'सिर्फ मंत्री य सांसद, विधायक भर नहीं हैं। जो लोग मेरे विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे बारे में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। जय मिश्र ने अपने भाषण में आंदोलन कर रहे किसानों को चेतावनी देते हुए कहा था- 'जिस दिन मैंने उस चुनौती के स्वीकार कर लिया उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर खीरी तक छोड़ना पड़ जाएगा, यह याद रहे।' इस भाषण के बायरल हुए वीडियो में वे यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि सामना करो आकर, 'हम आपको सुधार देंगे, देंगे मिनत लगेंगे गौतरलव है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के ऊपर हत्या सहित कई दूसरे आपराधिक मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। उन्होंने किसानों को उन मुकदमों की याद दिलाई थी और सबक सिखा देने की चेतावनी दी थी। दरअसल अजय मिश्र का जैसा अतीत है, उसे देखते हुए उनको मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ सांसद चुने गए बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी सरकार में मंत्री भी बना दिया। ठीक है, अगर मंत्री बना भी दिया तो इस भाषण के बाद ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई और उनके भाषण के टीक एक हफ्ते बाद तीन अक्टूबर को उनके नाम से

अजय मिश्र के बेटे किसानों को कुचल कर बाद में मारा है, उससे प्रदल्ले अजय मिश्र ने किसानों को जो उनके विलाप काले दिनों दिया गया

सुनकर लाखों लोग सहज उन्हें सुनने आ जाते थे

अटलजी प्रधानमंत्री बनें, यह सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि पूरे भारत की इच्छा थी। वर्षों तक विपक्ष के नेता रहते हुए भारत का अनेक बार भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान अपनी वाणी से प्रत्येक भारतीयों को जहां जोड़ा और भारत को समझा, वर्हाँ सदन के भीतर सत्ता में बैठे लोगों पर मां भारती के प्रहरी बनकर सदैव उनकी गलतियों को देश के सामने रखते रहे। भारतीय राजनीति में विपक्ष में रहते हुए जितने लोकप्रिय और सर्वप्रिय अटलजी रहे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी पड़ित जवाहरलाल नेहरू उतने लोकप्रिय नहीं हुए। अटलजी के आचरण और वचन में लयबद्धता और एकरूपता थी। वै जब तक सदन में विपक्ष या सत्ता में रहे तब तक सदन के राजनैतिक हीरो अटलजी ही रहे। इस बात को हम नहीं बल्कि तत्कालीन अनेक वरिष्ठ नेतागण स्वयं कहते थे। सन् 1996 में पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने, बाद में सन् 1999 में मात्र एक वोट से सरकार गिर जाने जैसी दुखद स्थिति में भी न वे स्वयं विचलित हुए, न पार्टी के सदस्यों को हार के कारण दुखी और हतप्रभ होने दिया। यह सब तभी संभव है जब व्यक्ति में आत्मबल हो और अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो। अटलजी ने कहा भी, हँखरीद-फरोखा और ऐसी कोई भी जोड़-तोड़ की सरकार बनती है तो उसे चिमटे से भी छूना पासंद नहीं करूंगा हृ इसके लिए विरोधी नेताओं ने भी सदन में उनकी प्रशंसा की। प्रत्येक भारतीय ने भी अटलजी के दर्द को महसूस किया। देश के लोगों के आशीर्वाद से सन् 1999 के चुनाव में फिर प्रधानमंत्री बने।

यहीं था अटलजी का अटल और विशाट व्यक्तित्व। अटलजी अक्सर कहा करते थे, रद्दोंस बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं इव यहीं कारण था वे भारत से बस लेकर लाहौर गए लेकिन जब पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो करगिल के युद्ध में उसे बुरी तरह पराजित भी किया। वे छोटे गजों के द्विमायती थे। उन्होंने बड़ी सरलता से छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड का गठन अपने कार्यकाल में कर दिया। भारत के गांवों को सड़क से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उसे फलीभूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर विश्व को संदेश दिया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं। अटलजी सिद्धांतवादी, विचार एवं व्यवहार से सरल और जमीन से जुड़े महान नेता थे। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी देश के हर दल के गजनीताओं और कार्यकाताओं के मन में अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। वह विपक्षी नेताओं का भी दिल जीत लेते थे। उनका मानना था कि भाजपा कार्यकाताओं की पार्टी है। जो नेता है, वह भी कार्यकर्ता है। उनका कहना था कि जो आज विधायक हैं, वह कल शायद विधायक नहीं रहें। सांसद भी सदैव नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को पार्टी बदल देती है, कुछ को लोग बदल देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का पद ऐसा है, जो बदला नहीं जा सकता। कार्यकर्ता होने का हमारा अधिकार छीना नहीं जा सकता। आज अटलजी हमरे बीच नहीं हैं, लेकिन जनसंघ के घोषणा-पत्र में लगातार जो बातें आती रहीं, उन सभी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी साकार कर रहे हैं। अटलजी को भारत रत्न से विभूषित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने केवल अटलजी का ही नहीं, भारत के करोड़ों लोग जो अटलजी के प्रशंसक थे, उनका सम्मान किया। अटलजी कहा करते थे, रस्सरकार गरीबों के लिए, सरकार समाज के लिए, सरकार राष्ट्र के लिए और सरकार एक-एक भारतीय के लिए होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी की सरकार आज अपनी योजनाओं से देश के गरीबों तक पहुंच रही है। रसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासर अटलजी के दिखाए गए मार्ग का प्रकटीकरण ही तो है।

अनिल जैन

अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को कुचल कर मार डालने की घटना एक सोची-समझी साजिश के तहत हुई है तो यह क्यों नहीं माना जाया जिस द्वारा सामिल में सभी ऐसी सामिल हो गयी हैं?

जाए कि इस साजिश में मत्रा भी शामिल हो सकत है? अजय मिश्र का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा इसलिए भी होना चाहिए कि एसआईटी ने अभी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट दखिल नहीं की है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है, जिसे प्रभावित किया जा सकता है। अजय मिश्र केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री है, जो अपनी आधिकारिक हैसियत से जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उनका इस्तीफा इसलिए भी होना चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे के कथित अपराध की एसआईटी जांच के बारे में सवाल पूछने पर एक पत्रकार को पीट दिया और मोबाइल फोन छीन लिया। सो, यह सिर्फ नैतिकता का मामला नहीं है, जिसके आधार पर मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, बल्कि धमकी देने, मंत्री के तौर पर गलत आचरण करने और एक साजिश में शामिल होने की संभावना के कारण इस्तीफा मांगा जा रहा है। अजय मिश्र से इस्तीफा मांगे जाने वाले उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने उन्हें मंत्री बनाए रखा है और उनकी पार्टी उनका बचाव कर रही है तो सिर्फ इसलिए कि उत्तर

हिस्सेदारी क्रमशः 67,7,52 तथा 34 प्रतिशत के आंकड़े के साथ कुछ उम्मीद जगाती है। किंतु कोविड-19 के कारण निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने नौकरियां गंवाई हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभ तभी हमारे श्रमिकों को मिल सकते हैं जब उनकी कुशलता में सुधार आए। किंतु अकुशल एवं अद्वैत क्षेत्र श्रमिकों को कुशल बनाने की आशा कम से कम निजी क्षेत्र से तो नहीं की जा सकती। जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को ही उठानी होगी। ऐसा लगा कि मोदी सरकार इस विषय को गंभीरता से ले गी। पहली बार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई। जुलाई 2015 से प्रारंभ स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 2022 तक 40 करोड़ लोगों को रोजगार पाने योग्य स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2016 से शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हार्डवेयर, फूट प्रोसेसिंग, फर्नीचर एवं फिटिंग, हाईक्रॉफ्ट, जेम्स और ज्वेलरी तथा लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसके तहत 2016 से 2020 की अवधि में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य था। किंतु इस अवधि में 50 लाख युवाओं को ही कुशल बनाया जा सका है। योजना के तहत देश भर में खोले गए 2500 केंद्रों में से अनेक बंद हो गए हैं। स्किल इंडिया मिशन मोदी सरकार की अनेक बहुप्रचारित योजनाओं की भाँति ही सरकारी विज्ञापनों में ही सफल है। सरकार इसके लिए समृच्छित बजट तक नहीं देती। ऑक्सफेम द्वारा जनवरी 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट 'पब्लिक गुड और प्राइवेट वेल्थ' में असमानता खत्म करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं की सार्वभौम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इनका निजीकरण बंद हो। सामाजिक सुरक्षा और पेशन तथा शिशु कल्याण सरकारी नीतियों का अंग हों। सरकारों की सभी योजनाएं महिलाओं के लिए समान रूप से लाभकारी हों। कर प्रणाली की समीक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सहभागी बनाई जाए। हमें कॉरपोरेट्स और सुपर रिच लोगों द्वारा किए जाने वाले कर अपवर्चन पर रोक लगानी होगी। इन पर अधिक करारोपण करना होगा। हाल ही में अमेरिका जैसे देश में एलेक्ज़ॉडिया ऑक्सिसओ कॉर्टेज, एलिजाबेथ वरिन तथा बर्नी सेंडर्स जैसे राजनेताओं ने धनपतियों पर भारी करारोपण का सुझाव देकर कर प्रणाली में सुधार के विषय को आम जनता के बीच बहस का मुद्दा बना दिया है। भारत में भी इस विषय पर खुली चर्चा होनी चाहिए।



